

[2023] 1 एस. सी. आर 317

एम/एस। मल्टीट लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड

और एक और

बी.

आय कर आयुक्त

(सिविल अपील सं। 10201-10202 2010)

3 जनवरी, 2023

[संजीव खन्ना और एम. एम. सुंदरेश, जे. जे.]

ब्याज कर अधिनियम, 1974 - एस. 2 (5-ए) और एस. 2 (5 - बी)-किराया-खरीद समझौते-अपीलकर्ता-निर्धारिती क्रेडिट संस्थान हैं।

एस का अर्थ। 2 (5 - क)-क्या अपीलकर्ता-निर्धारिती किराया-किराया-खरीद समझौतों के तहत भुगतान की गई खरीद किशतों में शामिल ब्याज घटक पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं-आई. टी. ए. टी. ने 13 जनवरी 1998 के सी. बी. डी. टी. परिपत्र संख्या 760 का उल्लेख किया और कहा कि किराया-खरीद समझौता एक समग्र लेनदेन है, और इसमें जमानत के तत्व हैं।

और बिक्री और अपीलकर्ता-निर्धारिती ब्याज कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं क्योंकि किराए की किशतें ब्याज कर के लिए प्रभार्य ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज नहीं हैं-उच्च न्यायालय ने आई. टी. ए. टी. के निष्कर्ष को यह कहते हुए उलट दिया कि किराया-खरीद किशत में "वित्त शुल्क" शामिल है, जो ब्याज के अलावा और कुछ नहीं है, और इसलिए, ब्याज घटक पर ब्याज कर लगाया जाता है-लेनदेन, हालांकि एक किराया-खरीद समझौते के रूप में शैलीबद्ध है, उच्च न्यायालय ने माना, वास्तव में एक वाहन की खरीद के लिए एक वित्त समझौता है-अपीलकर्ता द्वारा 13 जनवरी 1998 को जारी परिपत्र संख्या 760 पर अपीलकर्ता निर्धारिती द्वारा रिलायंस द्वारा रखा गया।

सीबीडीटी को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: सहारा इंडिया सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला श्रू जनरल के मामलों में कथन और अनुपात को देखते हुए प्रबंधक, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही नहीं है-13 जनवरी 1998 के परिपत्र संख्या 760 में, सी. बी. डी. टी. ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर विचार किया और उन्हें सलाह दी गई कि ऐसे लेनदेन के मामले में जो वास्तव में, किराया-खरीद की प्रकृति में हैं, किराया शुल्क की रसीदें ब्याज की प्रकृति में नहीं होंगी -

लेन-देन, मूल्यांकन अधिकारियों को विचार करने की आवश्यकता थी अन्य बातों के साथ-साथ गुण-दोषों को ध्यान में रखते हुए जारी करना-(i) समझौते की शर्तें; (ii) आपूर्तिकर्ता के बीच व्यवस्था की प्रकृति।

[2023] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परिसंपत्ति, किराया-खरीद कंपनी और परिसंपत्ति का अंतिम उपयोगकर्ता; और (iii) उन पक्षों का इरादा जो प्रारंभिक भुगतान, किराया-खरीद मूल्य आदि के निर्धारण में खुद को प्रकट करते हैं-हालांकि, जब किराया-खरीद कंपनी होती है

ऐसे अवक्रेता की ओर से कीमत या उसके एक बड़े हिस्से का भुगतान करता है जो वास्तविक खरीदार है लेकिन पूरी कीमत का भुगतान नहीं करता है, तो ऐसा समझौता ऋण के पुनः भुगतान के लिए प्रतिभूति की प्रकृति का है और अनिवार्य रूप से एक ऋण लेनदेन है-उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष को उलट दिया कि

आई. टी. ए. टी. ने कानून के एक विशिष्ट महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार किए बिना और इस प्रकार, तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप अनुचित था-आदेश

अपीलार्थी के मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धन को हटाते हुए आई. टी. ए. टी. द्वारा पारित, अलग रखा गया-मोटर वाहन अधिनियम 1988 - एस. 51.

ब्याज कर अधिनियम, 1974 - धारा 2 (7)-ब्याख्या और दायरा-किराया-खरीद समझौते के तहत वसूल किया गया ब्याज, यदि इसके तहत आता है एस. 2 (7) आयोजित किया गया: धारा 2 (7) की व्याख्या दो निर्णयों में की गई है, अर्थात् सहारा इंडिया सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के मामलों में।

महाप्रबंधक के माध्यम से लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एस को बहुत सीमित और सीमित अर्थ दिया है। 2 (7) ऋणों और अग्रिमों पर प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने वाले ब्याज के रूप में अधिनियम, और किसी अन्य ब्याज के रूप में नहीं, चाहे वह निवेश पर अर्जित ब्याज हो या रियायती विनिमय बिल के विलंबित भुगतान पर देय ब्याज।

किराया-खरीद-तत्व-आयोजित: किराया-खरीद समझौता

इसके दो तत्व हैं-जमानत का एक तत्व और बिक्री का एक तत्व अवक्रेता द्वारा किए गए किसी भी हस्तांतरण या बिक्री या किराया खरीद समझौते के किसी भी उल्लंघन से नागरिक और आपराधिक दोनों हो सकते हैं।

परिणाम।

कराधान-कराधान के मामले-आई. टी. ए. टी.-स्कोप द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्षों के साथ उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप-आयोजित: के निष्कर्ष आई. टी. ए. टी. द्वारा आम तौर पर दर्ज किए गए तथ्यों को निर्णायक माना जाता है-उच्च न्यायालय कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्णय करते समय तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप कर सकता है जब निष्कर्ष रिकॉर्ड पर सामग्री द्वारा समर्थित नहीं होते हैं, ताकि इसे विकृत माना जा सके-इसके लिए, उच्च न्यायालय को कानून का एक अलग महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करना चाहिए और उसके बाद ही सख्त मापदंडों को लागू करते हुए आई. टी. ए. टी. द्वारा तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना चाहिए।

कराधान के मामले-पूर्ववर्ती-पूर्ववर्ती एम/एस के रूप में एक कर अधिनियम से संबंधित निर्णयों के अनुपात को लागू करते समय सावधानी का नियम।

मुथूट लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड v.

आय कर आयुक्त

एक अन्य कर अधिनियम से संबंधित मामले में-सावधानी का यह नियम महत्वपूर्ण है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रूप से तब जब अधिनियम की भाषा और अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य अलग-अलग हों। भारत का संविधान-कला। 141 - एस. एल. पी.-बर्खास्तगी-आयोजित: यदि बर्खास्तगी सीमित है और प्रवेश स्तर पर है, तो यह एक बाध्यकारी पूर्ववर्ती यू/आर्ट का गठन नहीं करेगा। 141 संविधान से।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. किराया-खरीद समझौते के दो तत्व होते हैं-जमानत का एक तत्व और बिक्री का एक तत्व। तत्व का

बिक्री तब फल देती है जब समझौते की शर्तों को पूरा करने के बाद इच्छुक खरीदार द्वारा खरीद के विकल्प का उपयोग किया जाता है। तब तक सामान किराए पर दिया जाता है। कोई तर्क दे सकता है कि ए में

खरीद समझौता। मोटर वाहन अधिनियम के तहत पंजीकृत मालिक दुर्घटनाओं/यातायात चालान आदि के मामले में उत्तरदायी हो सकता है। लेकिन इस मामले में किसी भी तरह से, संपत्ति के स्वामित्व, यानी वाहन के संबंध में अपीलार्थियों-निर्धारिती के अधिकार को कम करता है। अवक्रेता द्वारा किए गए किसी भी हस्तांतरण या बिक्री या किराया-खरीद समझौते के किसी भी उल्लंघन से नागरिक के साथ-साथ आपराधिक परिणाम भी हो सकते हैं। सहारा इंडिया सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में महाप्रबंधक के माध्यम से कथन और अनुपात को देखते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स जीई में लिया गया दृष्टिकोण। कैपिटल ट्रांसपोर्टेशन, जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने ब्याज कर आयुक्त बनाम. एम/एस जी. ई. राजधानी परिवहन सही है और केरल उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण

विवादित फैसला इस अदालत के उपरोक्त फैसलों के अनुरूप नहीं है। [पैरा 14] [329-सी-एच] [2023] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. 13 जनवरी 1998 के परिपत्र संख्या 760 में, सीबीडीटी ने पाया कि उन्होंने इस मुद्दे पर विचार किया और उन्हें सलाह दी गई कि

ऐसे लेन-देनों के मामले में जो वास्तव में किराया-खरीद की प्रकृति के हैं, किराया शुल्क की रसीदें ब्याज की प्रकृति की नहीं होंगी। उन लेन-देनों में, जो वास्तव में, वित्तपोषण लेन-देन की प्रकृति में हैं, किराया शुल्क होना चाहिए ब्याज के रूप में माना जाता है, ब्याज कर के अधीन। दो लेन-देनों के बीच अंतर निर्धारित करने के लिए, मूल्यांकन अधिकारियों को अन्य बातों के साथ-साथ गुण-दोष को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता थी-(i) समझौते की शर्तें; (ii) संपत्ति के आपूर्तिकर्ता, किराए के बीच व्यवस्था की प्रकृति।

क्रय कंपनी और परिसंपत्ति का अंतिम उपयोगकर्ता; और (iii) में खुद को प्रकट करता है

पक्षकारों का इरादा जो निर्धारण

प्रारंभिक भुगतान, किराया निर्धारित करने की विधि-खरीद मूल्य आदि। हालांकि, जब किराया-खरीद कंपनी ऐसे किरायेदार की ओर से कीमत या उसके एक बड़े हिस्से का भुगतान करती है जो वास्तविक खरीदार है लेकिन पूरी कीमत का भुगतान नहीं करता है, तो ऐसा समझौता ऋण के पुनः भुगतान के लिए प्रतिभूति की प्रकृति में होता है और अनिवार्य रूप से एक ऋण लेनदेन होता है। [पैरा 16] [331-एफ-एच; 332-ए-बी]

3.1 . सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड में निर्णय किराया-खरीद समझौतों में किराए की वास्तविक प्रकृति से संबंधित है जैसा कि

बिक्री कर अधिनियम का संदर्भ। हालाँकि, वर्तमान मामले में, एक अधिनियम की धारा 2 (7) के साथ काम कर रहा है और उसकी व्याख्या कर रहा है, जिसकी व्याख्या दो निर्णयों में की गई है, अर्थात् सहारा इंडिया सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला थ्रू जनरल मैनेजर के मामले में, जिन्होंने अधिनियम की धारा 2 (7) को बहुत सीमित और सीमित अर्थ दिया है, क्योंकि ऋण और अग्रिम पर सीधे ब्याज प्राप्त होता है, न कि कोई अन्य ब्याज, चाहे वह निवेश पर अर्जित ब्याज हो या रियायती विनिमय बिल के विलंबित भुगतान पर देय ब्याज।

[पैरा 17] [332-बी-ई]

3.2 . कराधान इस बात पर निर्भर करता है कि प्रभार अनुभाग की भाषा और कर के चार कोनों के भीतर क्या कर लगाया जाता है।

चार्जिंग अनुभाग। इसलिए, एक कर अधिनियम से संबंधित निर्णयों के अनुपात को दूसरे कर अधिनियम से संबंधित मामले में एक उदाहरण के रूप में लागू करते समय सावधानी और सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी का यह नियम महत्वपूर्ण है और इसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, अधिक एम/एस।

मुथूट लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड v.

आय कर आयुक्त

अतः जब अधिनियम की भाषा और उद्देश्य और
[332-ई-एफ]

अधिनियमन का उद्देश्य अलग है। [पैरा 18]

4.1 . आई. टी. ए. टी. द्वारा आम तौर पर दर्ज तथ्यों के निष्कर्षों को निर्णायक माना जाता है। उच्च न्यायालय इसमें हस्तक्षेप कर सकता है

कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्णय करते समय तथ्य के निष्कर्ष जब निष्कर्ष रिकॉर्ड पर सामग्री द्वारा समर्थित नहीं होते हैं, ताकि उन्हें विकृत माना जा सके। इसके लिए, उच्च न्यायालय को कानून का एक अलग महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करना चाहिए और तभी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए।

सख्त मापदंडों को लागू करते हुए आई. टी. ए. टी. द्वारा तथ्य के निष्कर्ष। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने एक फ्रेम नहीं बनाया

कानून का विशिष्ट महत्वपूर्ण प्रश्न और इस प्रकार, तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप अनुचित है। इसका मतलब यह नहीं है कि कर अधिकारी पक्षों द्वारा दिए गए नामकरण की परवाह किए बिना लेनदेन के सही चरित्र और प्रकृति का पता लगाने के लिए आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने के हकदार नहीं हैं। [पैरा 19] [333-सी-ई]

4.2 . वर्तमान मामले में, इस विशिष्ट समय पर, रिमांड का आदेश पारित करना उचित नहीं होगा। होना ही है।

यह भी उल्लेख किया कि अधिनियम 31 मार्च 2000 से प्रभावी रूप से काम करना बंद कर दिया है। 21. विवादित फैसले को तदनुसार दरकिनार कर दिया जाता है। निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धन को अलग कर दिया जाता है और अपीलार्थी और अन्य मामलों के मामले में परिवर्धन को हटाने वाले आई. टी. ए. टी. द्वारा पारित आदेशों को बरकरार रखा जाता है। [पैरा 20,21] [333-जी; 334-ए]

269 2002 का]-निरस्त।

स्टेट बैंक ऑफ मैसूर बनाम। आई. टी. आयुक्त,

कर्नाटक-1, बेंगलूर (1989) 175 आई. टी. आर. 607 को रद्द कर दिया गया।

23] 1 एस. सी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आय कर आयुक्त V. चोलामंडलम

निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड (2008) 296 आईटीआर 601 को मंजूरी दी गई।
के. एल. जौहर एंड कंपनी (दोनों अपीलों में) V. डिप्टी

वाणिज्यिक कर अधिकारी, कोयम्बटूर III (दोनों में)

अपील) ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1082: [1965] 2 एस. सी. आर. 112;
सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम। केरल राज्य और

एक अन्य ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1178 [1966] 2 एस. सी. आर. 828; ब्याज
कर आयुक्त, नई दिल्ली बनाम। मेसर्स जी. ई. कैपिटल सर्विसेज इंडिया [उच्चतम न्यायालय का निर्णय

दिनांक 16 मई, 2008 को 2008 के एसएलपी (सी) संख्या 14202 में] और
एसोसिएशन ऑफ लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस

कंपनियों V. भारत संघ और अन्य (2011) 2 एस. सी. सी.
352 : [2010] 13 एस. सी. आर. 381-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1966] 2 एससीआर 828

पै

रा 7

संदर्भित किया गया है

(2009) 17 एससीसी 43

उस पर भरोसा करें

पै

रा 10

[2015] 12 एससीआर 243

उस पर भरोसा करें

पै

रा 10

[1965] 2 एससीआर 112

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

[2010] 13 एससीआर 381

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 102

10202 2010 से।

उच्च न्यायालय के 10/03/2008 दिनांकित निर्णय और आदेश से

आई. टी. ए. Nos.230 और 269/2002 में केरल के एनाकुलम में।

के साथ

सिविल अपील Nos.10203,10204,10205-10206,2010 का 10207,4

4904 , 4905 , 4906 , 4907 2014 का और 2011 का एसएलपी (सिविल) No.4441।

रुपेश कुमार, शशांक बाजपेयी, चिन्मायी चंद्रा

रघुनाथ, सुश्री रितिका सिन्हा, वी. के. मोंगा, ई. एम. एस. अनम, ए. एन. आर. श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

एम/एस। मूथूट लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड v.

आय कर आयुक्त

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजीव खन्ना, जे।

1. विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 4441 में दी गई छुट्टी

2011 .

2. सामान्य प्रश्न जो इस पर विचार करने के लिए उत्पन्न होता है

दीवानी अपीलों का समूह है: क्या अपीलार्थी-निर्धारिती किराया-खरीद समझौते के तहत भुगतान की गई किराया-खरीद किशतों में शामिल ब्याज घटक पर ब्याज-कर अधिनियम, 1974 1 के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं? 3. तथ्य, संक्षेप में, यह है कि अपीलकर्ता-निर्धारिती गैर-बैंकिंग वित्त और रिजर्व बैंक में पंजीकृत पट्टे पर देने वाली कंपनियां हैं।

भारत से। कुछ अपीलार्थी-निर्धारिती को किराया-खरीद वित्त कंपनियों के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। यह विवादित नहीं है कि अपीलकर्ता-निर्धारिती अधिनियम की धारा 2 (5-ए) के अर्थ के भीतर ऋण संस्थान हैं, जो निम्नानुसार है:

" (5 - (क) "ऋण संस्था" का अर्थ है -
(i) एक बैंकिंग कंपनी जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित)

उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट);

((ii) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4-ए में परिभाषित एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान;
((ग) धारा 3 के अधीन स्थापित राज्य वित्तीय निगम या

धारा 3-ए या राज्य की धारा 46 के तहत अधिसूचित संस्था

वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) और
((iv) कोई अन्य वित्तीय कंपनी;

अधिनियम की धारा 2 (5-बी) का उल्लेख करना भी अनिवार्य है, जो एक "वित्तीय कंपनी" को परिभाषित करती है और इसके दायरे में किराया-खरीद शामिल है।

वित्तीय कंपनियाँ:

" (5 - (ख) "वित्तीय कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो खंड (5-ए) के उपखंड (i), (ii) या (iii) में निर्दिष्ट कंपनी,

होने के नाते

संक्षेप में, 'द एक्ट'।

23] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((i) एक किराया-खरीद वित्त कंपनी, अर्थात् एक कंपनी

जो अपने प्रमुख व्यवसाय के रूप में किराए पर लेता है-खरीद

लेन-देन या ऐसे लेन-देन का वित्तपोषण;

XX "

XX

XX

4. अपीलार्थियों-निर्धारिती का तर्क है कि

समझौते में उल्लिखित तिथियों पर उल्लिखित। इसके अलावा, किरायेदार को वाहन की उचित देखभाल करनी होती है और इसे अच्छी स्थिति में रखना होता है। उसे सभी देय किराए, दरों, करों और खर्चों का भी भुगतान करना पड़ता है। अवक्रेता को वाहन को अपनी एकमात्र अभिरक्षा और कब्जे में समझौते में उल्लिखित पते पर या ऐसे अन्य स्थान पर रखना चाहिए जहां मालिक ने पहले लिखित रूप में सहमति दी हो। मालिक या कोई भी व्यक्ति उसके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत, किराए की अवधि के दौरान सभी उचित समय पर वाहन का निरीक्षण करने का हकदार है। अवक्रेता, किसी भी समय, मालिकों को अपनी लागत पर वाहन वितरित करके किराया-खरीद समझौते का निर्धारण कर सकता है। यदि किरायेदार किराए की किश्तों का भुगतान करने में विफल रहता है

निर्धारित समय के भीतर, दिवालिया हो जाता है, गिरवी रखता है या बेचता है, या प्रयास करता है

वाहन को गिरवी रखने या बेचने या अन्यथा अलग करने या स्थानांतरित करने के लिए, या कोई ऐसा कार्य या चीज़ करता है या पीड़ित करता है जिसके द्वारा या जिसके परिणामस्वरूप, वाहन को दूर किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है या कानूनी प्रक्रिया के तहत निष्पादित किया जा सकता है, या किराया-खरीद समझौते में उल्लिखित किसी भी शर्त का पालन करने या पालन करने में विफल रहता है, मालिक को तुरंत निर्धारित करने का अधिकार है।

समझौता और, उसके बाद, उस स्थान में प्रवेश करने का हकदार है जहाँ वाहन को रखा जाता है और उसे जब्त कर लिया जाता है, हटा दिया जाता है और फिर से कब्जा कर लिया जाता है। मालिक को सभी देय किश्तों, समझौते के उल्लंघन के लिए हर्जाने और वाहन के कब्जे को फिर से लेने की लागत के लिए मुकदमा करने का भी अधिकार है। मालिक, यदि सहमत हों, तो अवक्रेता को अपने नाम पर वाहन का पंजीकरण कराने की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते कि अवक्रेता मालिक द्वारा ऐसा करने के लिए जब भी आवश्यक हो, मालिक के नाम पर पंजीकरण हस्तांतरित करेगा, विशेष रूप से जब अवक्रेता 2 में से किसी का उल्लंघन करता है।

एम/एस। मुथूट लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड v.

आय कर आयुक्त [संजीव खन्ना, जे.]

समझौते की शर्तें, जिनके कारण मालिक वाहन को जब्त करने के लिए बाध्य हैं।

5. इन तथ्यों पर आई. टी. ए. टी. ने अपीलकर्ताओं की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि वे ब्याज पर ब्याज कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

किराया-खरीद किश्त में निहित घटक। आई. टी. ए. टी. ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 3 द्वारा 13 जनवरी 1998 को जारी परिपत्र संख्या 760 का उल्लेख किया और कहा कि किराया-खरीद समझौता

समग्र लेन-देन, और इसमें जमानत और बिक्री के तत्व हैं। ऊपर उल्लिखित किराया-खरीद समझौते के नियमों और शर्तों के आधार पर,

आई. टी. ए. टी. ने माना कि किराया-खरीद समझौते ऋण और अग्रिम से अलग हैं। किराया किश्तें कुछ अलग और अधिक हैं, न कि ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज जो उनसे लिया जाता है।

ब्याज कर।

6. आई. टी. ए. टी. ने किराया-खरीद अधिनियम, 1972 के प्रावधानों पर भी भरोसा किया था, जो हमारी राय में स्पष्ट रूप से गलत है क्योंकि उक्त अधिनियम को कभी भी लागू नहीं किया गया था और बाद में उसे निरस्त कर दिया गया था।

क्रय (निरसन) अधिनियम, 2005।

7. आयकर आयुक्त, कोचीन बनाम के मामले में केरल उच्च न्यायालय। एम/एस। मुथूट लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड ने 10 मार्च 2008 के विवादित फैसले द्वारा आई. टी. ए. टी. के निष्कर्ष को दरकिनार करते हुए कहा कि किराया-खरीद किश्त में "वित्त शुल्क" शामिल है, जो ब्याज के अलावा और कुछ नहीं है, और इसलिए ब्याज घटक पर ब्याज कर लगाया जाता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि लेन-देन, हालांकि एक किराया-खरीद समझौते के रूप में शैलीबद्ध है, वास्तव में एक है वाहन की खरीद के लिए वित्तीय समझौता। उधारकर्ता के रूप में किरायेदार से एक समान ब्याज दर ली गई थी। अवक्रेता, के भुगतान पर

किश्तों में, एक रुपये में वाहन खरीदने का विकल्प था, जो एक खाली औपचारिकता थी, क्योंकि वाहन पहले से ही उनके नाम पर पंजीकृत था। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 51 के अनुसार, पंजीकरण प्राधिकरण को पंजीकरण के प्रमाण पत्र में किराया-खरीद समझौते का विवरण दर्ज करना आवश्यक है। प्रत्यर्थी-निर्धारिती के पास डिफॉल्ट रूप से वाहन को पुनः प्राप्त करने का लाइसेंस था, लेकिन स्वामित्व प्राप्त करने के लिए उन्हें 3 के प्रावधानों के तहत नाम परिवर्तन के लिए आवेदन करना था।

4 2002 का आई. टी. ए. सं. 269।

5 संक्षेप में, 'एम. वी. अधिनियम'।

23] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एम. वी. अधिनियम। सीबीडीटी द्वारा 13 जनवरी 1998 को जारी परिपत्र संख्या 760 पर अपीलकर्ता-निर्धारिती द्वारा रखी गई निर्भरता को यह देखते हुए खारिज कर दिया गया कि सीबीडीटी ने पहले 25 मार्च 1996 को परिपत्र संख्या 738 जारी किया था जिसमें स्पष्ट किया गया था कि किराया-खरीद समझौते के तहत वसूल किया गया ब्याज अधिनियम की धारा 2 (7) के तहत आता है। निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा गया था। केरल राज्य और एक अन्य, एक निर्णय जो

हम बाद में जाँच करेंगे।

8. दिल्ली उच्च न्यायालय ने ब्याज कर आयुक्त बनाम. 1 सितंबर 2006 को तय मैसर्स जी. ई. कैपिटल ट्रांसपोर्टेशन ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें कहा गया है कि निर्धारिती ने ऋण या अग्रिम पर कोई ब्याज अर्जित नहीं किया है, ग्राहक/अवक्रेता द्वारा किराए के लिए भुगतान की गई किराया खरीद किश्त का कोई भी घटक नहीं है।

अधिनियम के तहत ब्याज कर के लिए प्रभार्य। इस स्तर पर, यह बताना प्रासंगिक हो सकता है कि आयकर आयुक्त, नई दिल्ली द्वारा आयकर आयुक्त, नई दिल्ली के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। मैसर्स जी. ई. कैपिटल सर्विसेज इंडिया 3, को इस न्यायालय ने 16 मई 2008 को खारिज कर दिया था। बर्खास्तगी सीमित और प्रवेश स्तर पर होने के कारण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत एक बाध्यकारी मिसाल नहीं होगी।

9. अधिनियम की धारा 2 (7), 1 अक्टूबर 1991 से प्रभावी संशोधन के बाद, निम्नानुसार है:

" (7) " ब्याज का अर्थ है ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज।

भारत और इसमें शामिल हैं

(क) किसी भी ऋण के अप्रयुक्त हिस्से पर प्रतिबद्धता शुल्क

भारत में लाभ उठाने के लिए स्वीकृत; और

(ख) वचन पत्रों और निकाले गए विनिमय पत्रों पर छूट या

भारत में निर्मित,

लेकिन शामिल नहीं है

(i) धारा 42 की उप-धारा (1-बी) में निर्दिष्ट ब्याज

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2);

6 ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1178

7 2006 का आई. टी. ए. सं. 1275।

8 2008 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 14202।

एम/एस। मुथूट लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड v.

आय कर आयुक्त [संजीव खन्ना, जे.]

((ii) ट्रेजरी बिलों पर छूट।

10. आयकर आयुक्त, कानपुर बनाम द्वारा अधिनियम की धारा 2 (7) की व्याख्या करते हुए इस न्यायालय के दो प्रत्यक्ष निर्णय हैं। सहारा

इंडिया सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड; और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला महाप्रबंधक के माध्यम से v. आयकर आयुक्त, पटियाला 10, जो प्रासंगिक हैं, और इस प्रकार, हम उन्हें कुछ विस्तार से संदर्भित करेंगे।

11. सहारा इंडिया में बचत और निवेश निगम

मुद्रास्फीति संबंधी उपाय और राजस्व संग्रह के लिए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने अधिनियम की धारा 2 (7) की जांच और व्याख्या करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा कि "ब्याज" अभिव्यक्ति को "ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज के रूप में एक प्रतिबंधात्मक अर्थ दिया जाना चाहिए, जिसमें प्रतिबद्धता शुल्क, वचन पत्रों और विनिमय पत्रों पर छूट शामिल है, लेकिन इसमें रिजर्व बैंक की धारा 42 (1-बी) में निर्दिष्ट ब्याज शामिल नहीं होना चाहिए। भारत अधिनियम, 1934 के साथ-साथ ट्रेजरी बिलों पर छूट"। धारा 2 (7) पहले भाग में कर योग्य ब्याज को परिभाषित करती है और ब्याज को केवल ऋण तक सीमित करती है।

और अग्रिम, और दूसरे भाग में, विशिष्ट अधिदेश द्वारा, वचन शुल्क और वचन पत्रों और ऋण पत्रों पर छूट शामिल है।

विनिमय करें। इस तरह से प्रावधान की व्याख्या करते हुए, यह माना गया कि विधायिका ने अपने विवेक में, दूसरे भाग में "ब्याज" शब्द के अर्थ को दो मर्दों तक बढ़ा दिया था, अर्थात् प्रतिबद्धता शुल्क और

वचन पत्रों और विनिमय पत्रों पर छूट। उक्त मामले में, प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने बॉन्ड और डिबेंचर में निवेश किया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रत्यर्थी-निर्धारिती द्वारा खरीदे गए इन बॉन्डों और डिबेंचरों पर ब्याज, "निवेश" के रूप में, अधिनियम की धारा 2 (7) के तहत ब्याज के रूप में कर योग्य नहीं है क्योंकि वे योग्य नहीं हैं और इन्हें "ऋण और अग्रिम पर ब्याज" के रूप में नहीं माना जा सकता है।

12. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में महाप्रबंधक (उपरोक्त) के माध्यम से,

इस न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के बीच मतभेद की जांच की थी एससीसी 43.

9 (2009) 17

10 (2015) 15 एससीसी 483।

23] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस पर अदालतें कि क्या छूट वाले विनिमय बिलों के भुगतान में चूक पर देय निश्चित प्रतिशत शुल्क को अधिनियम की धारा 2 (7) के अर्थ के भीतर ब्याज के रूप में माना जाना चाहिए। इस खाते में जमा की गई राशि अपीलार्थी बैंक द्वारा अपने ब्याज खाते में बुक की गई थी। निर्धारिती से सहमति जताते हुए इस न्यायालय ने कहा कि अधिनियम में 'ब्याज' की परिभाषा संकीर्ण है, और संपूर्ण है क्योंकि यह एक 'साधन और शामिल' परिभाषा है। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर बनाम में कर्नाटक उच्च न्यायालय का तर्क आई. टी. आयुक्त,

कर्नाटक-1, बेंगलोर "कि किसी बिल में छूट देना अग्रिम या ऋण का एक रूप है और इसलिए, देय धन के विलंबित भुगतान पर भुगतान किया गया मुआवजा ऋण और अग्रिम पर ब्याज है, को खारिज कर दिया गया था।

अधिनियम की धारा 2 (7) में सीमित कवरेज की अनदेखी करना। ऋण और अग्रिम, और भारत में तैयार या बनाए गए विनिमय के रियायती बिलों के बीच अंतर है। यदि छूट वाले विनिमय बिलों को भी भारत में किए गए ऋण और अग्रिम के रूप में माना जाना था, तो विनिमय बिलों पर छूट को शामिल करने के लिए "ब्याज" की परिभाषा को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

13. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में महाप्रबंधक (उपरोक्त) के माध्यम से लिया गया निर्णय भी इसकी व्यापक परिभाषा के बीच अंतर करता है। आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 2 (28 ए) के माध्यम से "ब्याज" अभिव्यक्ति यह देखने के लिए है कि अधिनियम के तहत उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति, यानी ब्याज कर अधिनियम, 1974, बहुत संकीर्ण और प्रतिबंधित है। आयकर के तहत

1 11 (1989) 175 आई. टी. आर. 607।

12 (2008) 296 आईटीआर 601।

एम/एस। मूथूट लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड v.

आय कर आयुक्त [संजीव खन्ना, जे.]

अधिनियम, 1961, ब्याज किसी भी तरह से देय हो सकता है। दूसरा, अधिनियम की धारा 2 (7) में निहित "चालू" शब्द के विपरीत, "के संबंध में" अभिव्यक्ति में अप्रत्यक्ष रूप से भी धन लेनदेन से उत्पन्न होने वाला ब्याज शामिल है, जो ऋण या अग्रिम से ब्याज के भुगतान से प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने का संकेत देता है। तीसरा, "उधार लिए गए किसी भी धन" की तुलना "ऋण या अग्रिम" से की जानी चाहिए। पूर्व अभिव्यक्ति में ऋण या अग्रिम के अलावा अन्य माध्यमों से उधार लिए गए धन शामिल होंगे। इस प्रकार, यह अधिनियम, आयकर अधिनियम, 1961 के विपरीत, एक बहुत ही संकीर्ण कर योग्य घटना पर केंद्रित है, जिसमें विनिमय के रियायती बिल के तहत देय राशि के भुगतान में चूक पर देय ब्याज शामिल नहीं है।

14. किराया-खरीद समझौते के दो तत्व होते हैं-जमानत का एक तत्व और बिक्री का एक तत्व। बिक्री का तत्व तब फलता है जब

खरीदने के विकल्प का उपयोग इच्छुक खरीदार द्वारा समझौते की शर्तों को पूरा करने के बाद किया जाता है। तब तक सामान किराए पर दिया जाता है। यह तर्क दिया जा सकता है कि किराया-खरीद में, ब्याज का एक तत्व अंतर्निहित है, लेकिन

जो देय है वह किराया राशि है न कि ब्याज। किरायेदार के पास वाहन या किराए पर लिए गए सामान को वापस करने का विकल्प होता है। यह एक नहीं है ऋण या अग्रिम देने का सरल लेन-देन जिस पर ब्याज देय है। वाणिज्यिक और कानूनी अर्थों में लेन-देन पक्षों के संबंधित अधिकारों के साथ कहीं अधिक जटिल हैं। भले ही किरायेदार के रूप में दर्ज किया गया हो

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 51 के तहत वाहन के मालिक, अपीलकर्ता-निर्धारिती का नाम भी पंजीकरण पुस्तिका में दर्ज किया जाता है, जो किराया-खरीद समझौते की मान्यता में है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत पंजीकृत मालिक दुर्घटनाओं/यातायात चालान के मामले में उत्तरदायी हो सकता है। आदि। लेकिन यह, किसी भी तरह से, संपत्ति के स्वामित्व, यानी वाहन के संबंध में अपीलार्थियों-निर्धारिती के अधिकार को कम नहीं करता है। अवक्रेता द्वारा किया गया कोई हस्तांतरण या बिक्री या किराया-खरीद समझौते का कोई उल्लंघन

नागरिक के साथ-साथ आपराधिक परिणाम भी हो सकते हैं। सहारा इंडिया सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कथन और अनुपात को देखते हुए (ऊपर) और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला महाप्रबंधक (ऊपर) के माध्यम से, मैसर्स जी. ई. कैपिटल में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण।

परिवहन 13 (ऊपर), जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अनुसरण किया गया है ब्याज कर आयुक्त v. एम/एस जी. ई. पूंजी परिवहन 14 14,

यह सही है और विवादित फैसले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण इस अदालत के उपरोक्त फैसलों के अनुरूप नहीं है।

13 2006 का आई. टी. ए. 1275। 14 2006 का आई. टी. ए. 1280।

23] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. हालाँकि, राजस्व के विद्वान वकील ने सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड (उपरोक्त) पर भरोसा किया है, जो निर्णय भी लिया गया था।

खरीद समझौते, हालांकि बिक्री कर अधिनियम के संदर्भ में। हालाँकि, इस अदालत ने यह भी कहा कि विधायी मार्गदर्शन के अभाव में भी, बिक्री कर अधिकारी किराए को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। इस निर्णय का पालन सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड (ऊपर) के मामले में जे. सी. शाह, जे. द्वारा लिखित बहुमत निर्णय के साथ किया गया था, जिसमें कहा गया था कि के. एल. जौहर एंड कंपनी (ऊपर) में संविधान पीठ का निर्णय उन समझौतों से संबंधित है जहां फाइनेंसर ने माल के पूर्व मालिक को शेष राशि का भुगतान किया है और उसके बाद किराया प्राप्त किया है। ग्राहक से खरीद समझौता, जिसके तहत ग्राहक

निर्धारित किराए की सभी किश्तों के भुगतान पर माल का मालिक बन जाता है और भुगतान पर माल खरीदने के अपने विकल्प का उपयोग करता है। नाममात्र की कीमत पर। किराया-खरीद लेनदेन के एक अन्य रूप में, माल ग्राहक द्वारा खरीदा जाता है, जो किराया-खरीद समझौते और संबद्ध दस्तावेजों को निष्पादित करने के विचार में, माल के कब्जे में रहता है, जो फाइनेंसर 15 ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1082 द्वारा भुगतान की गई राशि का भुगतान करने के दायित्व के अधीन है।

एम/एस। मूथूट लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड v.

आय कर आयुक्त [संजीव खन्ना, जे.]

ग्राहक की ओर से मालिक या विक्रेता को। वित्तपोषक किराया-खरीद समझौता प्राप्त करता है जो उसे ग्राहक द्वारा किराया-खरीद समझौते की शर्तों का पालन करने में विफलता की स्थिति में माल को जब्त करने का लाइसेंस देता है। लेन-देन का वास्तविक प्रभाव आसपास की परिस्थितियों के आलोक में विचार किए गए समझौते की शर्तों से निर्धारित किया जा सकता है। कुछ मामलों में, वास्तविक सौदा माल की प्रतिभूति पर ऋण होगा। यदि वस्तुओं की प्रामाणिक और पूर्ण बिक्री है, जो दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित है, विक्रेता को बाद में और विशिष्ट रूप से काम पर रखने से पहले और स्वतंत्र है, तो लेनदेन निम्नानुसार नहीं हो सकता है:

इसे एक ऋण लेनदेन के रूप में माना जाता है, भले ही इसमें प्रवेश करने का कारण धन जुटाना था। उपरोक्त को दर्ज करते हुए, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्धारिती की अपील को बहुमत द्वारा यह देखते हुए अनुमति दी गई थी कि वे वित्तपोषकों का व्यवसाय कर रहे थे और मोटर वाहनों के साथ काम नहीं कर रहे थे। ग्राहक द्वारा खरीदा गया मोटर वाहन उसके नाम पर पंजीकृत था और हर भौतिक समय पर उसके नाम पर पंजीकृत रहा। बिक्री पत्र एक औपचारिक दस्तावेज था जो निर्धारिती के नाम पर वाहन का पंजीकरण करके इसे प्रभावी नहीं बनाया गया था और यहां तक कि मोटर वाहन का बीमा भी इस तरह से किया जाना था जैसे कि ग्राहक ही मालिक हो।

16. इससे पहले कि हम उस तर्क और संदर्भ की जांच करें जिसमें स्पष्टीकरण दिया गया था, हम सीबीडीटी द्वारा जारी दो परिपत्रों का उल्लेख करना चाहेंगे। सी. बी. डी. टी. ने 25 मार्च 1996 के परिपत्र संख्या 738 के माध्यम से कहा था कि किराया-खरीद लेनदेन आम तौर पर वित्तपोषण के व्यवसाय में लगी कंपनियों द्वारा किए गए वित्त लेनदेन की प्रकृति में होते हैं, और खरीद वित्त कंपनियों को नियुक्त करने के लिए उपार्जित या उत्पन्न होने वाले वित्त शुल्क ब्याज की प्रकृति में होते हैं जैसा कि परिभाषित किया गया है।

अधिनियम की धारा 2 (7) और इसलिए, ब्याज कर के लिए प्रभावी। हालाँकि, 13 जनवरी 1998 के बाद के परिपत्र संख्या 760 में, सी. बी. डी. टी. ने पाया कि उन्होंने इस मुद्दे पर विचार किया और उन्हें सलाह दी गई कि ऐसे लेनदेन के मामले में जो वास्तव में, किराया-खरीद की प्रकृति में हैं, किराया शुल्क की रसीदें ब्याज की प्रकृति में नहीं होंगी। में। ऐसे लेन-देन जो सारतः वित्तपोषण की प्रकृति के हों।

लेन-देन, किराया शुल्क को ब्याज के रूप में माना जाना चाहिए, ब्याज कर के अधीन। दोनों लेन-देनों के बीच अंतर निर्धारित करने के लिए, मूल्यांकन अधिकारियों को अन्य बातों के साथ-साथ गुण-दोष को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर विचार करना आवश्यक था-(i) समझौते की शर्तें; (ii)

परिसंपत्ति के आपूर्तिकर्ता, किराया खरीद कंपनी और परिसंपत्ति के अंतिम उपयोगकर्ता के बीच व्यवस्था की प्रकृति; और (iii) इरादा [2023] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रारंभिक भुगतान के निर्धारण में प्रकट होने वाले पक्षों में से,

किराया-खरीद मूल्य आदि के निर्धारण की विधि। हालांकि, जब किराया-खरीद कंपनी ऐसे किरायेदार की ओर से कीमत या उसके एक बड़े हिस्से का भुगतान करती है जो वास्तविक खरीदार है लेकिन भुगतान नहीं करता है पूर्ण मूल्य, तब ऐसा समझौता ऋण के पुनः भुगतान के लिए प्रतिभूति की प्रकृति में होता है और अनिवार्य रूप से एक ऋण लेनदेन होता है। संदर्भ था

सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में निर्णय दिया गया। 17. जैसा कि ऊपर देखा गया है, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड (उपरोक्त) में यह निर्णय किराया-खरीद समझौतों में किराए की वास्तविक प्रकृति से संबंधित है

बिक्री कर अधिनियम के संदर्भ में। हालांकि, वर्तमान मामले में, हम अधिनियम की धारा 2 (7) के साथ काम कर रहे हैं और उसकी व्याख्या कर रहे हैं, जिसकी व्याख्या दो निर्णयों में की गई है, अर्थात् सहारा इंडिया सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (उपरोक्त) और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के मामले में महाप्रबंधक (उपर्युक्त) के माध्यम से, जिन्होंने अधिनियम की धारा 2 (7) को बहुत सीमित और सीमित अर्थ दिया है, जो सीधे ऋण और अग्रिम पर उत्पन्न होने वाले ब्याज के रूप में है, न कि किसी अन्य ब्याज के रूप में, चाहे वह निवेश पर अर्जित ब्याज हो या रियायती विनिमय बिल के विलंबित भुगतान पर देय ब्याज।

18. कराधान प्रभार अनुभाग की भाषा और प्रभार अनुभाग के चार कोनों के भीतर कर में क्या लाया जाता है, इस पर निर्भर करता है। इसलिए, एक कर अधिनियम से संबंधित निर्णयों के अनुपात को दूसरे कर अधिनियम से संबंधित मामले में एक उदाहरण के रूप में लागू करते समय सावधानी और सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी का यह नियम महत्वपूर्ण है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रूप से तब जब अधिनियम की भाषा और अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य अलग-अलग हों। यह अनुपात है - एसोसिएशन ऑफ लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज V में इस न्यायालय द्वारा कुछ हद तक व्यक्त किया गया है। भारत संघ और अन्य 1, जिसमें

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (12) के साथ पठित धारा 65 (105) (जेड. एम.) द्वारा सेवा कर के उद्घाटन के संदर्भ में, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को कर के दायरे में लाया गया। उक्त अधिनियम के संदर्भ में, इस न्यायालय ने वित्तीय पट्टा और परिचालन पट्टा के बीच अंतर करना उचित समझा और यह अभिनिर्धारित किया कि पहले मामले में प्रदान की गई सेवाएं कर योग्य होंगी, जबकि दूसरा कर दायरे से बाहर होगा। इस संदर्भ में, यह देखा गया कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अनिवार्य रूप से ऋण देने वाली कंपनियां हैं, लेकिन वे इसके अलावा भी कर सकती हैं।

(2011) 2 एससीसी 352।

एम/एस। मूथूट लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड v.

आय कर आयुक्त [संजीव खन्ना, जे.]

अतः, उपकरण पट्टे पर देने, किराया-खरीद वित्त और निवेश के व्यवसाय में रहें। जमानत के मामले में जिसे "किराया" कहा जाता है, बेली को संपत्ति का कब्जा और बदले में इसका उपयोग करने का अधिकार दोनों प्राप्त होते हैं।

पारिश्रमिक। दूसरी ओर, उपकरण पट्टे पर देना दीर्घकालिक वित्तपोषण है जो उधारकर्ता को ऋण में एकमुश्त भुगतान के बिना धन जुटाने में मदद करता है।

पहला उदाहरण। यहाँ, "ब्याज" तत्व की तुलना पट्टे/किराए के लिए विचार से नहीं की जा सकती है, जो किराए के लिए पारिश्रमिक (विचार) की प्रकृति में है।

19. आई. टी. ए. टी. द्वारा आम तौर पर दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों का इलाज किया जाता है।

20. उपरोक्त कानूनी स्थिति को देखते हुए, हो सकता है कि हमने मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन अधिकारी के पास भेज दिया हो। उपरोक्त अनुपात और तर्क के आलोक में सभी लेन-देनों की जांच करें,

निर्धारिती और अवक्रेता से विस्तार से तथ्यों का पता लगाना। हालांकि, इस विशिष्ट समय पर, हमें नहीं लगता कि रिमांड का आदेश पारित करना उचित होगा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह अधिनियम 31 मार्च, 2000 से प्रभावी नहीं रहा है। 17 कर्नाटक वक्फ बोर्ड बनाम देखें। अंजुमन-ई-इस्माइल मदरिस-उन-निसवान, (1999) 6 एस. सी. सी. 343; और सी. डोडुनारायण रेड्डी (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा और अन्य बनाम सी. जयराम रेड्डी (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य द्वारा, (2020) 4 एससीसी 659।

रिपोर्ट

ए.

21. उपरोक्त को दर्ज करते

हुए, हम वर्तमान अपीलों की अनुमति देते हैं और

विवादित निर्णयों को अलग कर दें।
निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धन को अलग कर दिया जाता है और आई. टी. ए. टी. द्वारा
अपीलार्थी-मेसर्स के मामले में परिवर्धन को हटाने के आदेश पारित किए जाते हैं। मुथूट लीजिंग एंड फाइनेंस
लिमिटेड और अन्य मामलों को बरकरार रखा गया है। वर्तमान मामले के तथ्यों में,

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

बिभूति भूषण बोस

(सहायक: नेहा शर्मा, एलसीआरए)